साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Global School Of Excellence, Obedullaganj

वर्ष : 9, अंक : 40 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 22 मई 2024 से 28 मई 2024 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

झारसुगुड़ा में नियमों को ताक पर बेचा जा रहा एल्युमीनियम कचरा, एनजीटी ने आरोपों की जांच के दिए निर्देश

नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने झारसुगुड़ा में नियमों को ताक पर रख अवैध रूप से बेचे जा रहा एल्यूमीनियम के कचरे की जांच के निर्देश दिए हैं। आरोप है कि ओडिशा के झारसुगुड़ा में रुनाया रिफाइनिंग एलएलपी अवैध रूप से एल्यूमीनियम का कचरा बेच रही है। यह भी आरोप है कि कंपनी ने कथित तौर पर एल्यूमीनियम कचरे से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के तीसरे चरण का पालन नहीं किया है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है।

एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के सदस्य सचिव को उन दावों की जांच करने को कहा है। अदालत ने सीपीसीबी को यह जांचने को कहा है कि क्या यह शिकायत सही है और क्या यह इकाई पर्यावरणीय क्षति का कारण बन रही है। अगर ऐसा है तो ट्रिब्यूनल ने सीपीसीबी से उचित कानूनी कार्रवाई करने को भी कहा है। एल्युमीनियम अपशिष्ट पुनर्चक्रण, एल्युमीनियम कचरे के पुनः उपयोग की एक प्रक्रिया है। एल्युमीनियम मैल, एल्युमीनियम के पिघलने का एक उपोत्पाद, इसमें एल्युमीनियम, इसके ऑक्साइड, मिश्रधातु तत्व ऑक्साइड और कभी-कभी हैलोजेनाइड्स, कार्बाइड और नाइट्राइड होते हैं। पुणे में व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा ग्रीन बेल्ट का उपयोग, एनजीटी ने आरोपों की जांच के दिए आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने संयुक्त समिति से उन आरोपों की जांच का आदेश दिया है, जिसमें दावा किया गया था कि कोंढवा में एक ग्रीन बेल्ट का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। 17 मई 2024 को दिया यह आदेश महाराष्ट्र में पुणे के कोंढवा में स्थित एक ग्रीन बेल्ट के व्यावसायिक उद्देश्य से जुड़ा है। आरोपों की जांच के लिए जो संयुक्त समिति बनाई गई है उसमें पुणे के जिला मजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर शामिल होंगें। कोर्ट ने समिति से इस मामले में जांच के बाद एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी

कहा है। कोर्ट के निर्देशानुसार यह समिति इस साइट का दौरा कर जानकारी एकत्र करेगी। यदि उन्हें ग्रीन बेल्ट में किसी तरह के बदलाव या क्षति के संकेत मिलते हैं तो वो उस विषय में दो महीनों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट पश्चिमी बेंच के सामने प्रस्तुत करेगी।

गौरतलब है कि यह मामला कोणार्क पूरम सहकारी हाउसिंग सोसायटी के निवासियों के द्वारा भेजी पत्र याचिका के आधार पर पंजीकृत किया गया था। इसमें उन्होंने शिकायत की थी कि पुणे में करिया बिल्डर ने 800 फ्लैट और रो हाउस के साथ एक आवासीय परियोजना विकसित की है।

रिकॉर्ड के अनुसार, कोणार्क पूरम के पीछे के पूर्वी हिस्से को ग्रीन बेल्ट के रूप में दिखाया गया है और एक नाला उद्यान के लिए अलग रखा गया है। हालांकि, निवासियों ने देखा कि इस हरित पट्टी का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, जिसमें कई पेड़-पौधे जेसीबी जैसी भारी मशीनों द्वारा उखाड़ दिए गए हैं। स्थानीय निवासियों और अन्य लोगों द्वारा इस मामले में कई बार शिकायत करने के बावजूद, अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

देश में गर्मी का प्रकोप, जलाशयों के जलस्तर में 35 फीसदी तक की गिरावट

जलाशयों के जलस्तर में 35 फीसदी तक की गिरावट आ चुकी है, ऐसे में जल संकट आसन्न है, जैसा कि इस साल हम बेंगलूरु में देख चुके हैं। देश के एक बड़े हिस्से में लू (स्पश) का प्रकोप चल रहा है। इससे लोगों की सेहत और उत्पादकता पर खतरा गंभीर हो सकता है। विश्व बैंक के एक अध्ययन के मुताबिक, देश का करीब 75 फीसदी कार्यबल कृषि और निर्माण क्षेत्र में गर्मी का सीधे सामना करने वाले श्रम पर निर्भर करता है। इसके मुताबिक साल 2030 तक गर्मी के प्रकोप से जुड़ी उत्पादकता में गिरावट की वजह से दुनिया भर में कुल होने वाली नौकरियों के नुकसान में अकेले भारत का योगदान करीब 43 फीसदी तक हो सकता है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि लू (स्पश) का प्रसार और घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यह फैलाव साल 2009 के नौ राज्यों से बढ़कर साल 2020 में 23 राज्यों तक (2020 महामारी का वर्ष था जब लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गई थीं) हो गया। इसी अवधि में लू के औसत दिनों की संख्या तेजी से बढ़ते हुए 7.4 दिन से 32.2 दिन तक पहुंच गई। यह उत्साहजनक है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने इस समस्या का संज्ञान लिया है और तत्परता से कदम उठाए गए हैं। उदाहरण के लिए साल 2016 से ही, जब लू से 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, केंद्र सरकार ने लू की रोकथाम और प्रबंधन के लिए राज्यों में कार्य योजना बनाने के लिए एक व्यापक ढांचे के रूप में राष्ट्रीय दिशानिर्देश तैयार किए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने निर्धारित किया है कि किसी इलाके में लू की घोषणा तब की जानी चाहिए, जब वहां वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ हो, सामान्य अधिकतम तापमान कुछ भी हो। इस मामले में सबसे उपयोगी दस्तूर यह अपनाया जाता है कि भारतीय मौसम विभाग लू की एक चेतावनी जारी करता है और इससे बचने के लिए क्या करें, क्या न करें का एक मानक पैकेज होता है। नियोक्ताओं ने इस मामले में कुछ कदम उठाए। गर्मी के संपर्क वाले काम को रात के थोड़े ठंड वाले घंटों के लिए टाल दिया दिया गया, एक ऐसा बदलाव जिसे कुछ समय पहले कृषि श्रमिकों ने अपनाया था। इन सबका नतीजा यह हुआ कि लू से संबंधित मौतों की संख्या 2015 के 2040 से तेजी से घटकर 2020 में केवल 27 रह गई है। वैसे तो ये संख्या सराहनीय हैं, लेकिन आगे के लिए बड़ी चुनौती यह है कि लू प्रबंधन को किस तरह से एक सतत अनिवार्यता के रूप में विस्तारित और संस्थागत बनाया जाए। इसके लिए सिर्फ लू की चेतावनी और परामर्श जारी करने से काम नहीं चलने वाला; सूक्ष्म और वृहद नीति स्तरों पर ठोस और व्यावहारिक नीतियां अपनाने की जरूरत है। उदाहरण के लिए जलाशयों के जलस्तर में 35 फीसदी तक की गिरावट आ चुकी है, ऐसे में जल संकट आसन्न है, जैसा कि इस साल हम बेंगलूरु में देख चुके हैं।

जलवायु परिवर्तन के निशाने पर एवोकाडो, उपयुक्त क्षेत्रों में 41 फीसदी की गिरावट का अंदेशा

न्यूयार्क। एवोकाडो एक ऐसा फल जो विदेशों के साथ-साथ भारत में भी लोकप्रिय होता जा रहा है। आकार, रंग और बनावट में कुछ अलग सा दिखने वाला यह फल सेहत के लिए बेहद फायदेमंद समझा जाता है। हालांकि इस फल पर भी जलवायु परिवर्तन की नजर लग चुकी है।

क्रिश्चियन एड ने अपनी नई रिपोर्ट 'गेटिंग स्मैश्ड द क्लाइमेट डेंजर फेसिंग एवोकाडो' में खुलासा किया है कि जलवायु में आते बदलावों की वजह से एवोकाडो पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में क्रिश्चियन एड ने अपनी रिपोर्ट में तेजी से उत्सर्जन में कटौती के साथ-साथ किसानों को और अधिक समर्थन दिए जाने की वकालत की है। इसके गुणों की बात करें तो एक तरफ जहां इसमें कैलोरी बेहद कम होती हैं वहीं इसमें कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन सी, स्वस्थ वसा, फाइबर जैसे पोषक तत्वों के साथ एंटीऑक्सिडेंट गुण मौजूद होते हैं। यही वजह है कि इसे सुपरफूड की श्रेणी में भी रखा जाता है। गौरतलब है कि इस लोकप्रिय सुपरफूड को उगाने के लिए ढेर सारे पानी की आवश्यकता होती है, जिस वजह से पर्यावरण पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। देखा जाए तो पानी की बेहद आवश्यकता इसे विशेष रूप से जलवायु में आते बदलावों के लिए संवेदनशील बनाती है। रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि जैसे-जैसे दुनिया गर्म और शुष्क होती जा रही है, एवोकैडो उगाने के सबसे अच्छे क्षेत्र भी सिकुड़ रहे हैं।

आशंका है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से 2050 तक दुनिया में एवोकाडो की खेती के सबसे उपयुक्त क्षेत्रों में 41 फीसदी तक की गिरावट आ सकती है। उदाहरण के लिए मेक्सिको के मुख्य एवोकाडो उत्पादक क्षेत्र मिचोआकेन को 2050 तक एवोकाडो उत्पादक क्षेत्र में 59 फीसदी की कमी से जूझना पड़ सकता है। हालांकि यदि वैश्विक तापमान में होती वृद्धि को दो डिग्री सेल्सियस में सीमित भी कर लिया जाए तो भी प्रभावों में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा।

कुछ क्षेत्र दूसरों की तुलना में होंगे कहीं ज्यादा प्रभावित- ऐसा नहीं है कि यह प्रभाव केवल मेक्सिको तक ही सीमित रहेंगें। रिपोर्ट में आशंका जताई है कि स्पेन, चिली और कोलंबिया के मौजूदा प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में भी स्पष्ट तौर पर बदलती जलवायु का असर देखने को मिलेगा। इसकी वजह से उत्पादक क्षेत्रों में गिरावट आ सकती है। हालांकि यह प्रभाव काफी हद तक उत्सर्जन और उसको कम करने के लिए किए गए प्रयासों पर निर्भर करेगा। मतलब की जलवायु परिदृश्य जितना खराब होगा, एवोकाडो के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र उतनी तेजी से सिकुड़ेंगे। यदि दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक देश मेक्सिको को देखें तो 2050 तक उसके संभावित उत्पादक क्षेत्रों में 31 फीसदी की कमी आ सकती है। यह कमी तब भी देखने को मिलेगी जब तापमान में होती वृद्धि को दो डिग्री सेल्सियस के भीतर रोक दिया जाए। हालांकि यदि तापमान में पांच डिग्री सेल्सियस की कमी होती है तो उत्पादक क्षेत्रों में 43 फीसदी की कमी आ सकती है। इसकी वजह से एवोकाडो उद्योग और उसपर निर्भर लोगों की जीविका खतरे में पड़ सकती है। बुरुंडी के एक किसान जोलिस बिगिरिमाना ने रिपोर्ट में किसानों के सामने पैदा हो रही दिक्कतों पर प्रकाश डाला है। उनके मुताबिक एवोकाडो की खेती कर रहे किसानों को जलवायु में आते बदलावों की वजह से गंभीर परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। उनका कहना है कि, हम गर्म तापमान, भारी बारिश और कटाव का सामना कर रहे हैं, जो किसानों की पैदावार और आय को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। हमारे पास बुरुंडी में बारिश का एक छोटा सा मौसम होता है, और उस समय के दौरान, एवोकाडो किसान अपने पौधों को पानी देते हैं।

उनका आगे कहना है कि, जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम अब अधिक गंभीर हो गया है और इसका असर हमारी पैदावार पर पड़ रहा है। अब हमें फसलों को पानी देने में बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, जिससे हमारी आय प्रभावित हुई है। यह हमारी आजीविका के लिए भी खतरा बन रहा है।

कमजोर किसानों को मदद की है दरकार आंकड़ों के मुताबिक 2022 में, यूके दुनिया में एवोकाडो का सातवां सबसे बड़ा आयातक था। वो इस फल का 3.31 फीसदी हिस्सा आयात कर रहा था। इस रिपोर्ट में ब्रिटिश जनता की राय को भी शामिल किया गया है। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार को विकासशील देशों में टिकाऊ खेती का समर्थन करना चाहिए, जिससे ब्रिटेन की खाद्य आपूर्ति पर जलवायु संकट के प्रभावों को कम किया जा सके। इस बारे में 63 फीसदी लोगों ने सहमति जताई थी।

एवोकाडो के इतिहास पर नजर डालें तो मेसोअमेरिकन लोगों के आहार, पौराणिक कथाओं और संस्कृति में एवोकाडो का एक महत्वपूर्ण स्थान था। खाद्य इतिहासकारों के मुताबिक आज से करीब 10,000 साल पहले मध्य मेक्सिको, और ग्वाटेमाला में इसके खाए जाने के प्रमाण मिले हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह फल सबसे पहले अफ्रीका में उत्पन्न हुआ, फिर वहां से उत्तरी अमेरिका और फिर मध्य अमेरिका में पहुंचा।

शोधकर्ताओं का मानना है कि करीब 5,000 साल पहले एवोकाडो की खेती शुरू हुई। उसके बाद यह फल मेक्सिको, पेरू, इंडोनेशिया, कोलंबिया, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, हवाई, केन्या, हैती, चिली, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया में भी पैदा होना शुरू हो गया। यदि 2022 के आंकड़ों पर गौर करें तो मेक्सिको ने करीब 25.3 लाख टन एवोकाडो की पैदावार की, जिससे वह देश दुनिया भर में एवोकाडो का शीर्ष उत्पादक बन गया। इसके बाद एवोकाडो उत्पादन में कोलंबिया (10.9 लाख टन) दूसरे और पेरू 8.7 लाख टन के साथ तीसरे स्थान पर है।

एक बात तो तय है कि यदि उत्सर्जन में कटौती के लिए सरकारों की ओर से कार्रवाई नहीं की गई तो एवोकाडो को अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ सकता है। एक बात तो तय है कि यदि उत्सर्जन में कटौती के लिए सरकारों की ओर से कार्रवाई नहीं की गई तो एवोकाडो को अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में क्रिश्चियन एड ने सरकारों से उत्सर्जन में तत्काल कटौती करने और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में तेजी लाने का आह्वान किया है।

उन्होंने उन कमजोर किसानों को अधिक वित्तीय सहायता देने की बात भी कही है, जो अपनी जीविका के लिए एवोकाडो पर निर्भर हैं। इससे वो बदलती जलवायु का सामना करने के काबिल बन सकेंगे। क्रिश्चियन एड से जुड़ी मारियाना पाओली ने जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे किसानों पर प्रकाश डालते हुए प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से कहा है कि विकासशील देशों में किसान पहले ही जलवायु में आते बदलावों का खामियाजा भुगत रहे हैं। हालांकि वे अपने परिवारों का भरण-पोषण करने के लिए बेहतर जलवायु पर निर्भर हैं। ऐसे में उन्हें इस बदलते माहौल के अनुकूल ढलने के लिए कहीं ज्यादा वित्तीय समर्थन की आवश्यकता है।

जोधपुर में कारखानों से निकल रहा केमिकल युक्त जानलेवा पानी, एनजीटी ने अधिकारियों से मांगा जवाब

जोधपुर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने अधिकारियों से केमिकल युक्त पानी के मुद्दे पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। आरोप है कि जोधपुर में कारखानों के हानिकारक केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। पूरा मामला राजस्थान के जोधपुर जिले का है।

इस मामले में 15 मई, 2024 को दिए अपने निर्देश में ट्रिब्यूनल ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और बालोतरा के कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को सेंट्रल बेंच के सामने अपने जवाब दाखिल करने को कहा है। गौरतलब है कि इस बारे में 16 मार्च, 2024 को बालोतरा नामक पत्रिका में एक खबर प्रकाशित हुई थी। इस खबर के मुताबिक डोली-अराबा क्षेत्र से निकलता केमिकल युक्त पानी बालोतरा के कल्याणपुर तक पहुंच गया है। इससे ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। कई दिन बीत जाने के बावजूद अधिकारियों ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इस खबर में जल अधिनियम, 1974 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के उल्लंघन के मुद्दे को भी उठाया गया है।

एनजीटी ने फॉर्मल्डिहाइड फैक्ट्रियों के संबंध में हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मांगी सफाई- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य लोगों को उचित पर्यावरणीय मंजूरी के बिना यमुनानगर में चल रही फॉर्मल्डिहाइड बनाने वाली फैक्ट्रियों के संबंध में जवाब देने का निर्देश दिया है। 15 मई 2024 को दिए आदेश के तहत इन लोगों को अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले अपना हलफनामा कोर्ट में दाखिल करना होगा। इस मामले में अगली सुनवाई 30 अगस्त, 2024 को होनी है। मामला यमुनानगर में नियमों को ताक पर रख चल रही फॉर्मेल्डिहाइड इकाइयों से जुड़ा है, जो बिना किसी पर्यावरणीय मंजूरी के चल रही हैं। आवेदक के वकील का कहना है कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार, इन कारखानों के संचालन के लिए पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्राप्त करना आवश्यक है। उन्हें ईसी प्राप्त किए बिना काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे (सीकेआईसी) के प्रभाव क्षेत्र में पड़ने वाले अपने सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करने का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य परिवहन संबंधी बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, औद्योगिक क्षेत्रों को बंदरगाहों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों और महत्वपूर्ण आंतरिक इलाकों से जोड़ना है। विशेष रूप से, परियोजना चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे के हिस्से के रूप में चेय्यूर-वंदावसी-पोलूर सड़क और ईस्ट कोस्ट लिंक रोड के चेय्यूर-पनय्यूर खंड को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। यह परियोजना 29 जनवरी, 2021 को शुरू हुई थी। यह जानकारी राजमार्ग और लघु बंदरगाह विभाग की ओर से तमिलनाडु राजमार्ग विभाग द्वारा दायर एक रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि इस परियोजना में किसी नई सड़क का निर्माण शुरू करने की जगह मौजूदा सड़क को अपग्रेड और चौड़ा करने की बात कही गई है। ईसीआर लिंक तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) में ओडियूर झील के ऊपर से गुजरता है, जिसे एक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। हालांकि, ईसीआर लिंक के इस हिस्से के लिए सीआरजेड से मंजूरी प्राप्त नहीं की गई है, क्योंकि बैकवाटर खंड में सड़क का किसी तरह का कोई नियोजित सुधार नहीं हुआ है। रिपोर्ट का यह भी कहना है कि इस परियोजना के लिए फंडिंग को एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा मंजूरी दी गई।

अतिवृष्टि तथा बाढ़ से उत्पन्न होने वाली स्थितियों से निपटने के लिए एहतियात के रूप में पुख्ता इंतजाम

इंदौर (नगर प्रतिनिधि) इंदौर जिले में मानसून काल की निकटता को दृष्टिगत रखते हुए अतिवृष्टि तथा बाढ़ से उत्पन्न होने वाली स्थितियों से निपटने के लिये आपदा प्रबंधन के संबंध में चर्चा हेतु आज कलेक्टर कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने एहतियात के रूप में किए जा रहे इंतजामों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में अभी से ऐसी तैयारियां रखी जाए जिससे कि आपदा से त्वरित रूप से निपटने में मदद मिले। बैठक में बताया गया कि इस वर्ष जिले के सांवेर, महू और देपालपुर मुख्यालय पर भी होमगार्ड और एसडीआरएफ के बचाव एवं राहत दल मौजूद रहेंगे, जिससे की सूचना मिलने पर त्वरित ही क्षेत्र में इन दलों को भेजा जा सकेगा। जिले के पर्यटन स्थलों पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे।

बैठक में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सुनील मेहता, डीसीपी इंदौर श्री हंसराज सिंह, इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आर.पी. अहिरवार, अपर आयुक्त नगर निगम श्री सिद्धार्थ जैन, अपर कलेक्टर श्री गौरव बेनल तथा श्री रोशन राय सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में बताया गया कि आगामी समय में अतिवृष्टि, बाढ़ तथा इससे उत्पन्न स्थितियों से निपटने के लिए एहतियात के रूप में पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पूर्व सूचना तथा आकस्मिक स्थिति के दौरान सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर कार्यालय, नगर निगम, पुलिस मुख्यालय, एमपीईबी सहित अन्य कार्यालयों में आपदा नियंत्रण केंद्र (कंट्रोल रूम) स्थापित किये जायेंगे। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने निर्देश दिए कि मानसून के दौरान बिजली की आपूर्ति सतत बनाए रखी जाए। यशवंत सागर के गेट खोलने के पूर्व नागरिकों को पूर्व सूचना दी जाए। खदानों में विशेष निगरानी रखी जाए तथा उनके संचालकों से फेंसिंग कराई जाए। शहर में पानी निकासी की पर्याप्त व्यवस्था रखें। जलजमाव वाले स्थानों को पूर्व से चिन्हित कर एहतियात के रूप में तैयारी रखें। पूल और पुलियाओं पर विशेष ध्यान रखें। वहां चेतावनी संबंधी बोर्ड भी लगाए जाएं। तालाबों के पाल की मरम्मत पर भी विशेष ध्यान दिया जाये। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने कहा है कि पहुंच विहीन गांवों की सूची पूर्व से ही तैयार कर लें तथा वहां पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का भंडारण किया जाए। बैठक में बताया गया कि होमगार्ड द्वारा पर्याप्त संख्या में बचाव एवं राहत दल बनाए जा रहे हैं। बैठक में बताया गया कि इस बार विकासखंड मुख्यालयों पर भी बचाव एवं राहत दल मौजूद रहेंगे। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने कहा कि मानसून के दौरान शुद्ध पेयजल की उपलब्धता बनाए रखी जाए। आकस्मिक स्थिति के दौरान बनाए जाने वाले राहत शिविरों के लिए स्थानों का चयन अभी से कर लिया जाय। मानसून के दौरान जिले के जलीय पर्यटन क्षेत्रों के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जा रहे हैं, जिससे कि सुरक्षा के व्यापक प्रबंध वहां पर रह सकें। ऐसे पर्यटन केंद्रों पर चेतावनी संबंधी बोर्ड लगाए जाने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में निर्देश दिये गये कि शहर के ऐसे क्षेत्र जहां पूर्व में पानी भरता रहा है ऐसे स्थानों को चिन्हित कर पानी भरने के कारणों का पता लगाया जाये। नगर निगम पानी भरने के कारण पता कर बाधक अतिक्रमण और अन्य रूकावट दूर करें।

भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजा ऐसा फंगस जो प्लास्टिक का बेहद जल्द कर सकता है सफाया

नई दिल्ली। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा फंगस खोजा है जो सिंगल यूज प्लास्टिक का भी बेहद जल्द सफाया कर सकता है। यह खोज चेन्नई के भारतीदासन और मद्रास विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा की गई है, जिसके नतीजे अंतराष्ट्रीय जर्नल नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित हुए हैं।

शोधकर्ताओं ने 'क्लैडोस्पोरियम स्पैरोस्पर्मम' नामक इस फंगस को सूक्ष्म जीवों से संक्रमित माइक्रोप्लास्टिक्स के तैरते मलबे से अलग किया है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा इस पर की गई रिसर्च से पता चला है कि यह फंगस आमतौर पर डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग बनाने में उपयोग होने वाले पॉलिमर को बड़ी तेजी से तोड़, उसका वजन कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि इससे पहले भी ऐसे फंगसों की पहचान की गई है, जो प्लास्टिक को नष्ट करने में मदद कर सकते थे, लेकिन प्लास्टिक को तोड़ने की उनकी गति धीमी थी। ऐसे में वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक को तेजी से नष्ट करने में मददगार फंगस की पहचान के लिए शहरी कचरे के ढेर और दूषित पानी पर तैरते प्लास्टिक के टुकड़ों पर पाए गए 33 फंगस प्रजातियों की जांच की है। इनमें से 28 फंगस ऐसे थे, जो बेहद कम घनत्व वाली पॉलीथीन (एलडीपीई) को तोड़ सकने की क्षमता रखते थे। जब इन फंगसों का परीक्षण किया गया तो इन सभी में 'क्लैडोस्पोरियम स्पैरोस्पर्मम' नामक फंगस ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया।

इसके बाद वैज्ञानिकों ने बेहद कम घनत्व वाली पॉलीथीन (एलडीपीई) के एक छोटे टुकड़े को फंगस कल्चर में डाला और इसकी तुलना एलडीपीई के उस टुकड़े से की जिसका इलाज नहीं किया गया था। स फंगस ने प्लास्टिक से चिपकने और विशेष एंजाइम जारी करने के लिए मायसेलिया नामक छोटे जड़ जैसे भागों का उपयोग किया। इन एंजाइमों ने प्लास्टिक को छोटे टुकड़ों में बदल दिया। इसकी वजह से प्लास्टिक के टुकड़े की संरचना ढह गई, उसमें दरारें, गड्ढे और छिद्र बन गए। साथ ही सतह खुरदरी हो गई। इसकी वजह से प्लास्टिक के टुकड़े की संरचना ढह गई, उसमें दरारें, गड्ढे और छिद्र बन गए। साथ ही सतह खुरदरी हो गई। नतीजन इन बदलावों की वजह से जहां प्लास्टिक के टुकड़े का वजन एक सप्ताह में 15.2 फीसदी तक कम हो गया। वहीं 31 दिनों में इसमें 50 फीसदी तक की गिरावट आ गई। वहीं दूसरी तरफ प्लास्टिक के जिस टुकड़े को फंगस कल्चर में नहीं डाला गया, उसके वजन में कोई बदलाव या कमी नहीं देखी गई। जो स्पष्ट तौर पर दर्शाता है कि यह फंगस प्लास्टिक के टुकड़े को नष्ट करने में मदद करता है।

गौरतलब है कि आज दुनिया में बढ़ता प्लास्टिक

कचरा एक बड़ी चुनौती बन चुका है। इसमें सिंगल यूज प्लास्टकी की बेहद अहम भूमिका रही है। बता दें कि इस बेहद कम घनत्व वाली पॉलीथीन (एलडीपीई) का उपयोग डिस्पोजेबल और किराना बैग के साथ-साथ खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में भी किया जाता है।

गंगा-यमुना से लेकर प्लेसेंटा तक में मिल चुके हैं प्लास्टिक के सबूत

आंकड़ों की मानें तो कुल प्लास्टिक उत्पादन में 60 फीसदी का योगदान यह एलडीपीई ही देता है। इतना ही पर्यावरण में लगातार बढ़ता इसका कचरा अनिगिनत समस्याएं भी पैदा कर रहा है। प्लास्टिक के महीन कण आज हमारे भोजन, पानी यहां तक की जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, उसमें तक घुल चुके हैं। बता दें कि हाल ही में वैज्ञानिकों को गंगा-यमुना के जल में भी माइक्रोप्लास्टिक्स की मौजूदगी के सबूत मिले थे। प्लास्टिक के कई कण ऐसे हैं जो हमारे शरीर में भी अपनी पैठ बना चुके हैं। एक अन्य रिसर्च के हवाले से पता चला है कि लोग हर सप्ताह तकरीबन पांच ग्राम के बराबर माइक्रोप्लास्टिक के कण निगल रहे हैं, जो करीब-करीब एक क्रेडिट कार्ड के वजन के बराबर हैं। 2022 में पहली बार इंसानी फेफड़ों में माइक्रोप्लास्टिक्स के कण पाए गए थे। इसी तरह वैज्ञानिकों को अब तक इंसानी रक्त, फेफड़ों के साथ नसों में भी माइक्रोप्लास्टिक के अंश मिल चुके हैं। वहीं जर्नल एनवायरनमेंट इंटरनेशनल में प्रकाशित एक अध्ययन में अजन्मे शिशुओं के प्लेसेंटा यानी गर्भनाल में भी माइक्रोप्लास्टिक के होने के सबूत मिले हैं। मतलब की धरती, आकाश, समुद्र, ऊंचे पहाड़ और दूर ध्रुवों तक भी प्लास्टिक पहुंच चुका है। इतना ही नहीं वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक में 16,325 केमिकल्स के होने की भी पुष्टि की है। इनमें से 26 फीसदी केमिकल ऐसे हैं जो इंसानी स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए चिंता का विषय हैं। ऐसे में जिस तरह दिनों-दिन प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उससे निजात पाने के लिए सभी विकल्पों पर विचार करना जरूरी है, ताकि दुनिया को कभी वरदान समझे जाने वाले इस अभिशाप से जल्द से जल्द छुटकारा मिल सके।

लू (तापघात) के प्रकोप से बचाव हेतु सुझाव

इंदौर इंदौर जिले में बढ़ते हुये तापमान को देखते हुये लू (तापघात) के प्रकोप से बचाव हेतु एडवायजरी जारी की गई है। लू (तापघात) से बचाव हेतु नागरिकों से अपील की गई है कि लू (तापघात) के प्रकोप से बचाव एवं उपचार के लिए जारी एडवायजरी में दिये गये सुझावों का पालन करें।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एस. सैत्या ने नागरिकों से कहा है कि लू (तापघात) के लक्षण दिखाई देते ही निकट के अस्पताल में संपर्क कर आवश्यक दवा का उपयोग सुनिश्चित करें। बचाव के उपाय करें। उन्होंने बताया कि ग्रीष्म ऋतु में लू लगने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। वृद्ध, बच्चे, खिलाड़ी, धूप में काम करने वाले श्रमिक सर्वाधिक खतरे में रहते हैं। पसीना न आना, गर्म-लाल एवं शुष्क त्वचा, मतली, सिरदर्द, थकान, चक्कर आना, उल्टियां होना, बेहोश हो जाना एवं पुतलियां छोटी हो जाना लू (तापघात) के प्रमुख लक्षण एवं संकेत हैं। डॉ. सैत्या ने कहा है कि गर्मी व लू से बचाव के लिए खूब पानी पिएं व खाली पेट न रहें, शराब व केफिन के सेवन से बचें, ठण्डे पानी से नहाएं, सर ढके व हल्के रंग के ढीले व पूरी बांह के कपड़े पहने, बच्चों को बंद वाहनों में अकेला न छोड़े, दिन में दोपहर 12 से शाम 04 के मध्य बाहर जाने से बचें, धूप में नंगे पाँव न चलें, बहुत अधिक भारी कार्य न करें। बाहर निकलना आवश्यक हो तो छतरी व धूप के चश्मे का उपयोग करें, धूप में निकलने से पहले कम से कम दो गिलास पानी अवश्य पिएं, बुखार व लू लगने पर निकट के अस्पताल में संपर्क कर आवश्यक दवा का उपयोग सुनिश्चित करें। ह्.क्रस. का घोल, नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी, फलों का रस इत्यादि का सेवन लाभदायक होता है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008